

KUMARI SELJA (Haryana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

**Demand for establishment of professional and regulatory  
mechanism in the Engineering field**

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): I thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak. Sir, the Engineering technology play a key role in the development and economic growth of our country. It elevates the standard of living, adds comfort to life and brings jobs and homes to men. This is the reason for the high privilege of engineers in society.

Engineering is the largest segment of the Indian industry. There are 10,396 engineering institutes in India. But only a few institutes are imparting quality education. AICTE is the only system set out for the qualitative improvement in technical education, maintenance of norms and standards in engineering education. But the area of operations of AICTE is limited. There is no Professional or Statutory Council to check and measure the professional ethics of engineers. It is highly essential to establish a Statutory Body which imparts high standard of engineering education, grants recognition and accreditation to engineering colleges, grants registration to engineering graduates, prescribing professional conduct and etiquette, propriety, with disciplinary jurisdiction, like NMC, BCI, INC etc., which are functioning as the professional regulatory bodies in the respective areas.

Hence, my appeal is that necessary steps may be taken to establish a Professional, Statutory and Regulatory System in the engineering field also. Thank you.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

**Demand to bring Cooperative banks under the purview of RBI**

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, सारे देश में सहकारी बैंकों एवं सोसायटियों की बिगड़ती परिस्थितियों को सुधारने के लिए पूर्ववर्ती भारत सरकार ने प्रो. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। उसकी सिफारिश (अनुशंसा) पर नाबार्ड द्वारा सरकारी बैंकों

[श्री कैलाश सोनी]

के अंतर्गत काम करने वाली साख सहकारी समितियों को जिनकी रिकवरी 30 परसेंट तक थी, पुनः संस्थाओं को खड़ा करने हेतु आर्थिक सहायता दी एवं प्रदेश सरकारों के साथ एग्रीमेंट किया कि सहकारी बैंकों एवं समितियों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, केवल कृषक एवं जमाकर्ता संस्था चलाएंगे। बिना पैसा दिए सोसायटियों को कर्ज मुक्ति के लिए बाध्य किया जा रहा है जिससे किसानों की अंश पूंजी को खतरा हो गया है। इस कारण सरकारी बैंक सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि सोसायटियों में सहकारी बैंकों का पैसा लगा हुआ है। चूंकि सारे सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के लाइसेंसी हैं, इसलिए इन्हें रिजर्व बैंक के अंतर्गत किया जाए, जिससे सहकारिता, जो ग्रामीण अर्थ रचना की रीढ़ है, वह सुरक्षित रहे, अन्यथा सहकारी समितियां एवं बैंक खरते में आ जायेंगे। सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए।

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

**श्री सकलदीप राजभर** (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

**श्री अजय प्रताप सिंह** (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

CHAIRMAN: Mr. Navaneethakrishnan, an observation has already been made to this effect. You are not supposed to come to the Table. You can do so only after the session.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: I am sorry, Sir.

#### **Demand for shifting of the Passport Office from Meerut Cantonment to Meerut city**

**श्रीमती कान्ता कर्दम** (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आती हूं। हमारे यहां मेरठ में एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र है, जो मेरठ कैंट में स्थित है। इस बिल्डिंग की हालत बहुत ही जर्जर है। आम जनता के लिए पासपोर्ट ऑफिस में पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है और न ही शौचालय की व्यवस्था है। पासपोर्ट सेवा केन्द्र में ए.सी. की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है जिसके कारण आए दिन कम्प्यूटर्स खराब रहते हैं। इस कारण से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और एक ही काम के लिए बार-बार पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कैंट क्षेत्र में होने के कारण यहां मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं है जिसके कारण भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है।